बी डी एल सीएसआर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2021-22)

Submitted to

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

Submitted by

INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE
Shameerpet, Hyderabad

कार्यकारी सारांश

बीडीएल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बीडीएल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च कर रही है। सीएसआर के तहत मुख्य ध्यान क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा और साक्षरता, कौशल विकास और स्वच्छता आदि हैं। बीडीएल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिलों / अल्पविकसित क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों को शुरू किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर बजट ₹ 1812.61 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

परियोजना-वार प्रभाव नीचे दिया गया है

परियोजना 1: विजयनगरम में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं

विजयनगरम जिले के सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण और सीखने के माहौल को बढ़ाने के उद्देश्य से, विभिन्न हितधारकों, जिसमें जन प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल थे, ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर स्मार्ट कक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर धन सुरक्षित किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बीडीएल ने विजयनगरम जिले में 34 प्राथमिक और 6 ऊपरी प्राथमिक स्कूलों में 40 स्मार्ट कक्षा प्रणालियों की स्थापना के लिए ₹ 100 लाख की सीएसआर वित्तीय सहायता प्रदान की।

परिणाम: बीडीएल ने विजयनगरम जिले के चयनित 40 सरकारी स्कूलों में 40 KYAN स्मार्ट कक्षा प्रणालियों को स्थापित करके परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त किया। इस परियोजना से कुल 2500 प्राथमिक और ऊपरी प्राथमिक स्कूल के छात्रों को लाभ हुआ, जो विविध विषय सामग्री के साथ जुड़े और प्रतिदिन स्मार्ट कक्षा सत्रों में भाग लिया। नतीजतन, स्कूलों ने प्रतिदिन 3-4 स्मार्ट कक्षा सत्र आयोजित किए, जिससे छात्रों को समृद्ध शैक्षिक अनुभव प्रदान हुए और उनकी मूलभूत संख्यात्मक कौशल, पर्यावरण विज्ञान अवधारणाओं की समझ, साथ ही अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता में वृद्धि हुई।

प्रभाव: इस परियोजना ने विजयनगरम जिले, आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा शिक्षण और सीखने के माहौल को बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा मानकों में सुधार, स्कूल नामांकन में वृद्धि, अनुपस्थिति में कमी और सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हुई।

परियोजना 2: राजन्ना सिरसिल्ला के सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों का निर्माण

लड़कियों के शौचालय सुविधाओं के महत्व को पहचानते हुए, राजन्ना-सिरसिल्ला जिले में जिला मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन से सीएसआर धन सहायता सक्रिय रूप से मांगी। उनके प्रयास सफल रहे क्योंकि उन्हें ₹ 200 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग 39 चयनित सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों के निर्माण के लिए किया गया। इन शौचालयों का निर्माण केवल बीडीएल की उदार वित्तीय सहायता के कारण संभव हुआ। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू हुई और 2021-22 तक पूरी हुई।

परिणाम: इस परियोजना का उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया क्योंकि इसने राजन्ना-सिरसिल्ला जिले में स्थित 39 सरकारी स्कूलों में स्कूली बच्चों के लिए विशेष रूप से शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित कीं। नतीजतन, सरकारी स्कूलों में उपलब्ध शौचालय सुविधाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में, कुल 3000 स्कूली बच्चे, लड़के और लड़कियां, प्रतिदिन शौचालय सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

प्रभाव: राजन्ना-सिरसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों के निर्माण ने महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति दरों में सुधार और स्कूल छोड़ने की दरों में कमी शामिल है। यह लाभकारी प्रभाव स्कूली बच्चों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित अलग शौचालयों की उपलब्धता के कारण है, जो उनके बीच गरिमा और गोपनीयता की भावना को बढ़ावा देता है। परिणामस्वरूप, स्कूली बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना ने युवा छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ाया है।

परियोजना 3: नौसेना अस्पतालों, दिल्ली में कोविड संबंधित उपकरणों की खरीद

बीडीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर के कई भारतीय नौसेना अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन चिकित्सा उपचारों की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करना था। बीडीएल के सीएसआर धन के माध्यम से प्रत्येक नौसेना अस्पताल के लिए अधिग्रहित चिकित्सा उपकरणों का विवरण, जिसकी राशि 300 लाख रुपए थी। भारतीय नौसेना बेनेवोलेंट (परोपकारी/कल्याण) ने विभिन्न चिकित्सा उपकरण खरीदे।

परिणाम: बीडीएल ने इस परियोजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें पांच INHS अस्पतालों, एक INS अस्पताल और एक डाइविंग स्कूल अस्पताल की चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न चिकित्सा उपकरण, डिवाइस और सुविधाएं प्रदान की गईं। परिणामस्वरूप, इस पहल ने कोविड-19 के उपचार प्रोटोकॉल में उल्लेखनीय सुधार किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके आश्रितों के जीवन को बचाया गया जो संक्रमित थे। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना ने इन अस्पतालों में उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के माध्यम से आउटपेशेंट, इनपेशेंट, आपातकालीन और सर्जिकल उपचारों की क्षमता को बढ़ाया।

प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने भारतीय नौसेना अस्पतालों में उपचार सुविधाओं के विकास को तेज करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। इस परियोजना ने चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये अस्पताल भविष्य में होने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति को संबोधित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों, उन्नत उपकरणों और बेहतर सुविधाओं की बढ़ी हुई उपलब्धता ने आपातकालीन उपचारों के लिए आवश्यक समय में उल्लेखनीय कमी की है। परिणामस्वरूप, उन्नत सुविधाओं ने न केवल अस्पताल सेवाओं की समग्र प्रभावशीलता में सुधार किया है, बल्कि भारतीय सेना और उनके आश्रितों से जुड़े कई लोगों के जीवन की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान की गई प्रगति ने सैन्य ढांचे के भीतर स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए एक नया मानक स्थापित किया है, जो भविष्य की किसी भी स्वास्थ्य संकट के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित करता है।

परियोजना 4: भानुर गाँव में जिला परिषद हाई स्कूल का निर्माण

जिला परिषद हाई स्कूल (ZPHS), भानुर, 1989 में एक सह-शिक्षा स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। यह शैक्षणिक संस्थान तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले में स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र, भानुर गाँव में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली

को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में, स्कूल में कुल 145 छात्रों का नामांकन है, जिसमें 75 लड़के और 70 लड़कियाँ शामिल हैं। शिक्षण स्टाफ में 9 सदस्य हैं, जबकि 3 गैर-शिक्षण स्टाफ सदस्य हैं। वर्षों से, स्कूल ने उल्लेखनीय शैक्षणिक सफलता हासिल की है। हालांकि, इसे कक्षा अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, बीडीएल ने ₹ 324 लाख की लागत से एक स्कूल भवन का निर्माण किया और आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं। यह परियोजना फरवरी 2020 में शुरू हुई और मार्च 2022 तक पूरी हुई।

परिणाम: इस परियोजना ने कक्षा VI से X तक के 145 छात्रों के लिए सीखने को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाकर अपने उद्देश्य को बड़ी प्रभावशीलता के साथ पूरा किया। स्कूल भवन के निर्माण के बाद, कक्षा निर्देश, पाठ्येतर गतिविधियों, खेल प्रावधानों, दोपहर के भोजन के दौरान छात्र सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच और शौचालय सुविधाओं में सुधार देखा गया। इन प्रावधानों ने शैक्षिक मानकों और छात्र सुविधाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

प्रभाव: बीडीएल द्वारा भानुर में जिला परिषद हाई स्कूल में स्कूल भवन के निर्माण की शुरुआत ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जैसे स्कूल नामांकन में वृद्धि, छात्रों की अनुपस्थिति में कमी और छात्रों के बीच शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि। इसके अतिरिक्त, इस प्रयास ने स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पौष्टिक मध्याह्न भोजन और खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करके बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके अलावा, भानुर गाँव में निष्पादित इस परियोजना ने न केवल शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन लाए हैं, बल्कि निवासियों के बीच भविष्य के लिए आशा और आशावाद की भावना भी पैदा की है। यह शिक्षा और समुदाय-संचालित पहलों के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उत्थान और सशक्त बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

परियोजना 5: लखनऊ में कोविड अस्पताल में योगदान

2021 में, कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बीच, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक पूर्ण सुसज्जित अस्थायी कोविड केंद्र स्थापित करने के लिए सक्रिय उपाय किए। इस पहल, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी अस्थायी कोविड केयर सेंटर रखा गया, महामारी की दूसरी लहर के गंभीर प्रभाव को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में थी। केंद्र के लिए स्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में आवंटित किया गया था, और निर्माण की समग्र जिम्मेदारी डीआरडीओ ने ली, जिसमें मुख्य निर्माण अभियंता (सीसीई), उत्तर ने दो सप्ताह के भीतर स्थापना को सफलतापूर्वक पूरा किया। केंद्र में 500 बेड, 40 केएलडी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन गैस आपूर्ति प्रणाली, गहन देखभाल इकाइयाँ, वेंटिलेटर, एक प्रयोगशाला, एक औषधालय और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ सुसज्जित थीं। डीआरडीओ ने पूरे संचालन अवधि (5 मई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के लिए संचालन को सुगम बनाया और चिकित्सा स्टाफ प्रदान किया। इस पहल के लिए लगभग पच्चीस करोड़ रुपये की कुल धनराशि को 60% पीएम केयर्स और 40% सीएसआर से जुटाया गया, जिसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद और अन्य पीएसयू जैसे संगठनों से योगदान शामिल था। पीएमओ के निर्देश के बाद, डीआरडीओ ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) से वित्तीय सहायता मांगी। अपील के जवाब में, बीडीएल ने ₹ 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डीआरडीओ को वितरित की। इस महत्वाकांक्षी उद्यम ने हजारों गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर चिकित्सा देखभाल और जीवन रक्षक उपचार प्रदान किया।

प्रभावशीलता: अस्थायी कोविड-19 अस्पताल की स्थापना के साथ उद्देश्य प्राप्त किया गया। डीआरडीओ के साथ कुशल सहयोग के माध्यम से, इस सुविधा पर बड़ी संख्या में कोविड मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया,

जिससे कई लोगों की जान बचाई गई। इस अस्थायी केंद्र की स्थापना के बाद, 5 मई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक हजारों गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल और जीवन रक्षक हस्तक्षेप प्रदान किए गए।

प्रभाव: लखनऊ में 500 बेड वाले अटल बिहारी वाजपेयी अस्थायी कोविड केयर सेंटर की स्थापना ने 5 मई, 2021 से दूसरी लहर के अंत तक कई कोविड-19 मरीजों को उपचार प्रदान किया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम हुआ। यह केंद्र तीसरी लहर की तैयारी में संभावित आपात स्थितियों को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद, कोविड-19 के बोझ को पूरी तरह से कम करने के बाद चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं अन्य स्वास्थ्य प्रणालियों को वैकल्पिक उपचारों के लिए हस्तांतरित कर दी गईं।

परियोजना 6: सिकंदराबाद के सैन्य अस्पताल और हैदराबाद के संनगर में ईएसआईसी अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की कमीशनिंग

अप्रैल और जुलाई 2021 में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान भारत में ऑक्सीजन आपूर्ति संकट का गंभीर प्रभाव पड़ा। देश भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कोविड-19 से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। संक्रमित मरीजों की भारी संख्या ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप बेड, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी हुई। तेलंगाना राज्य ने दूसरी लहर के दौरान महत्वपूर्ण चुनौती का सामना किया, जिसमें उच्च संक्रमण और मृत्यु दर का अनुभव हुआ। सिकंदराबाद में सैन्य अस्पताल और हैदराबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तीव्र ऑक्सीजन की कमी को संबोधित करने के लिए, बीडीएल ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए, कोविड-19 उपचार के लिए निरंतर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक की क्षमता 960 लीटर वाले ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की पहल की। ये स्थापनाएँ कोविड-19 की दूसरी लहर के अंत की ओर, जून 2021 से सितंबर 2021 तक, महामारी की तीसरी लहर और अन्य संभावित स्वास्थ्य संकटों की तैयारी में हुईं। बीडीएल ने दोनों अस्पतालों में इन दो ऑक्सीजन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए ₹ 188.80 लाख का व्यय किया।

परिणाम: यह परियोजना गंभीर देखभाल मरीजों का इलाज करने वाले ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और सिकंदराबाद के सैन्य अस्पताल को इष्टतम स्तर की ऑक्सीजन आपूर्ति के वांछित परिणामों को देने में सफल रही। इस परियोजना ने तेलंगाना राज्य में सैन्य अस्पताल और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चिकित्सा अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत किया। इसके अलावा, इस परियोजना ने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सक्षम की, जो इन अस्पतालों को किसी भी विनाशकारी स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना करने में मदद कर सकती है।

प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने हमारे स्वास्थ्य प्रणाली और इसके वितरण प्रोटोकॉल को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत किया है। ऑक्सीजन-उत्पादन संयंत्रों की स्थापना और ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणालियों जैसे चिकित्सा अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान ने तेलंगाना में सैन्य अस्पताल और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को सशस्त्र बलों के कर्मियों, ईएसआई-बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न मरीजों का समय पर इलाज करने में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का भारी बोझ ऑक्सीजन संयंत्रों द्वारा कम किया गया, जिसने अस्पतालों को 92-96% संतृप्ति ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए 5 से 15 LPM की दर से ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले गंभीर रूप से बीमार मरीजों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को प्रबंधित करने और बचाने की अनुमति दी।

परियोजना 7: हैदराबाद के संनगर में ईएसआईसी में कोविड पृथक्करण सुविधाओं की स्थापना

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (ईएसआईसी एमसी और एच), संनगर, हैदराबाद, एक 800 बेड का अस्पताल है जो तेलंगाना में ईएसआई योजना के तहत कवर किए गए 14 लाख से अधिक बीमाकृत व्यक्तियों की सेवा करता है। कोविड के दौरान इस अस्पताल ने कोविड और गैर-कोविड दोनों सेवाएँ प्रदान कीं। इस अस्पताल में प्रतिदिन 2400 से अधिक मरीजों का आना-जाना होता है। गैर-कोविड मरीजों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए जहां कोविड-19 मरीजों का इलाज किया जा रहा था, ईएसआईसी एमसी और एच ने परिसर में विभिन्न आठ रणनीतिक स्थानों पर फ्लैप बैरियर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, उन्होंने कोविड-19 आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत बीडीएल से सीएसआर धन के लिए संपर्क किया, और परिणामस्वरूप, आठ फ्लैप बैरियर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। फ्लैप बैरियर ने मरीजों और मरीजों के परिचारकों के प्रवाह को कोविड और गैर-कोविड उपचार क्षेत्रों में कम करने में मदद की, जबकि केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई जो इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अधिकृत थे। परियोजना की कुल लागत ₹ 170 लाख थी।

परिणाम: ईएसआईसी एमसी एंड एच ने रणनीतिक स्थानों पर 8 फ्लैप बैरियर लागू करके अनधिकृत व्यक्तियों या ईएसआईसी-बीमाकृत मरीजों के अत्यधिक परिचारकों के लिए पहुंच को नियंत्रित करने और कर्मचारी उपस्थिति की निगरानी के अपने परियोजना उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इन फ्लैप बैरियर को नियंत्रकों से जोड़ा गया है जो उनकी कनेक्टिविटी की लगातार निगरानी करते हैं और पहुंच के लिए उपयोग किए गए आरएफआईडी कार्ड से डेटा संचारित करते हैं। नियंत्रक आईटी सर्वर रूम में दो सर्वरों से जुड़े हैं, जो विश्लेषण के लिए आवश्यक पहुंच विवरण संग्रहीत करते हैं। इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली के लिए बैकअप के रूप में कार्य करता है, जो फ्लैप बैरियर के लिए उपयोग किए गए उसी एप्लिकेशन द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर कर्मचारी उपस्थिति के लिए चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करता है।

प्रभाव: इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जैसे ईएसआईसी एमसी एंड एच में ईएसआईसी-बीमाकृत व्यक्तियों और उनके साथियों की पहुंच के लिए निगरानी प्रणालियों में सुधार, अनधिकृत प्रवेश की रोकथाम, और कर्मचारी समयबद्धता को बढ़ावा देना। इन संवर्द्धनों ने ईएसआईसी-बीमाकृत मरीजों के डेटा के बेहतर प्रबंधन, कर्मचारी दक्षता और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को अनुकूलित करके परिचालन लागत को कम करने में योगदान दिया। यह पहल विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान लाभकारी थी, क्योंकि इसने कार्ड पहुंच प्रणाली के माध्यम से केवल पात्र सामान्य और ईएसआईसी-बीमाकृत व्यक्तियों के लिए उपचार की अनुमति देकर कोविड-19 और गैर-कोविड-19 दोनों मरीजों के प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया, जिसके परिणामस्वरूप परिसर में व्यक्तियों के बीच वायरस संचरण में कमी आई।